

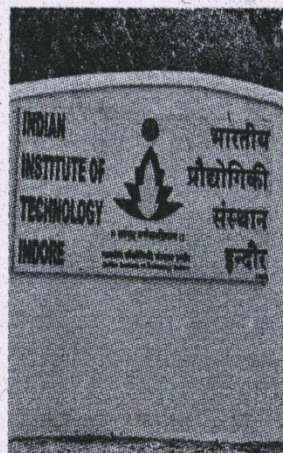
इंदौर आईआईटी की जमीन को जयराम की ना पर्यावरण मंत्रालय ने ठुकराया 200 एकड़ वनभूमि देने का प्रस्ताव, बड़ा झटका

पर्यावरण असंतुलन का हवाला दिया

सिटी रिपोर्टर @ इंदौर

सिमरोल में आईआईटी बनाने की योजना को केंद्र ने जोरदार झटका दिया है। सरकार ने कहा है कि जिस 500 एकड़ पर भवन बनाने की योजना है, उसमें से 200 एकड़ पर जंगल है। इसे आईआईटी को देने से इंदौर का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, लिहाजा अनुमति नहीं दे सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण व वन विभाग से अनुमति मांगी थी कि सिमरोल में प्रस्तावित प्लान में आ रही 200 एकड़ वन भूमि को आईआईटी के लिए मुक्त कर दें। इस पर विशेष अधिकार प्राप्त वन सलाहकार समिति ने असहमति जताई है। वन विभाग के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इस इलाके में 7164 हरे वृक्ष हैं।



इनकार के ये तर्क

जो जमीन मांगी उस पर सात हजार से अधिक पेड़ हैं और पर्यावरण संतुलन में मददगार हैं।

राज्य सरकार ने यह भी नहीं बताया कि इसके एवज में वन विकसित करने के लिए कहां जमीन दी जाएगी।

जो जमीन विद्वित की गई है, वह रिजर्व फॉरेस्ट के लिहाज से अहम है। उसे नहीं दिया जा सकता।

वन भूमि को इस तरह से किसी दूसरे उपयोग में तब्दील करने से देश में मलत उदाहरण पेश होगा।

एक और आपत्ति

जो जमीन घयनित है, उसमें 185 एकड़ महू

वेटेनरी कॉलेज की भी है। इस पर भी बहुत खवाल हो चुका है क्योंकि इसके

बदले बुराड़िया गांव में 179 एकड़ जमीन देने का

प्रस्ताव है। यह कॉलेज से 35 किमी दूर है जबकि सिमरोल की 22 किमी।

तीन संभावनाएं

मानव संसाधन मंत्रालय पर्यावरण विभाग को राजी करे।

राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि जमीन के बदले दूसरे स्थान पर इतना ही घन जंगल बनाया जाएगा।

पूरे प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार हो व स्थान बदला जाए।

2 साल पहले शिलान्यास: सिमरोल में 17 फरवरी 2009 को अर्जुन सिंह ने आईआईटी का शिलान्यास किया था।